

2487
8/4/16

पत्रांक- 2487 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिशद फुलवारीशरीफ

पटना, दिनांक

8/4/16

विषय :- माह फरवरी 2016 की मासिक समीक्षा टिप्पणी के संबंध में।

महाशय,

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आपके कार्यों की मासिक समीक्षा की जा रही है। माह फरवरी तक प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा से निम्न तथ्य विदित होते हैं :-

1. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग :-

- (i) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 271.01 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 271.01 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 238.58 लाख रुपये है, जो मात्र 88.03 प्रतिशत है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

2. 13वें वित्त आयोग :-

- (i) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 12.54 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 47.39 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 59.93 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 59.93 लाख रुपये है। जो मात्र 100 प्रतिशत है स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।
- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को कोई योजनाएं लंबित नहीं थी। वर्ष 2015-16 में अब तक 1 योजना ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 1 योजनाओं में से अभी तक 1 योजना पूर्ण हुई है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

14 वें वित्त आयोग :-

14 एवं वित्त आयोग के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 0.00 लाख रुपये उपलब्ध थे | वर्ष 2015-16 में 141.06 लाख रुपये विमुक्त हुए | कुल उपलब्ध 141.06 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 63.83 है | जो मात्र 45.25 प्रतिशत है |

3. राज्य योजना :-

- (i) राज्य योजना अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 919.59 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 80.42 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 1000.01 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 304.90 लाख है। जो की मात्र 30.49 प्रतिशत है |
- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को 3 योजनाएं लंबित थी। वर्ष 2015-16 में अब तक 6 योजनाएं ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 9 योजना में से अभी तक 3 योजना पूर्ण हुई है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि *निराशाजनक* है।

4. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (BRGF) :- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 5.50 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 0.00 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 5.50 लाख रुपये संसाधनों में से अद्यतन व्यय 1.74 लाख रुपये है, जो मात्र 31.64 प्रतिशत है।

- (ii) भौतिक प्रतिवेदन की समीक्षा करने से ज्ञात है कि दिनांक 01.04.2015 को 1 योजना लंबित थी। वर्ष 2015-16 में अब तक कोई भी योजना नहीं ली गयी है। इस प्रकार कुल कार्यरत 1 योजना पूर्ण नहीं हुई है। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि *निराशाजनक* है।

ठोस अवशिष्ट प्रबंधन :-

- (i) आपके शहर में कुल 28 वार्ड हैं, जिसमें से अभी तक 14 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य प्रारंभ हुआ है।
- (ii) सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिकरण पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन वांछित संख्या में मशीनों का क्रय नहीं किया गया है। शहर में कार्यरत सफाई कर्मियों की ससमय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमिट्रिक हाजिरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है, इसका अनुपालन अप्राप्त है। ठोस अवशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन एवं निष्पादन के लिए की जा रही कार्रवाई का प्रतिवेदन अपेक्षित है।

8. मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान :-

मुख्यमंत्री स्वच्छता अनुदान योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय में 0.00 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 80.42 लाख रुपये विमुक्त हुए। कुल उपलब्ध 80.42 लाख रुपये संसाधनों में से दूरभाष पर प्राप्त सूचना के अनुसार अद्यतन व्यय 57.75 लाख रुपये है।

5. उपयोगिता प्रमाण पत्र :-

आपके निकाय के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2014-15 तक की अवधि में कुल 2783.20 लाख की राशी विभाग द्वारा आवंटित की गयी थी जिसके आलोक में अभी तक कुल 1493.35 लाख रुपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा की गयी है और 741.54 लाख की राशी अभी तक समायोजित के लिए लंबित हैं। अगले 7 दिनों के अंदर इसका समायोजन कराया जाय। (1) उपलब्ध कराये गये सूची में वर्णित letter no. 69 dated 07.03.13 एवं letter no 41 dated 18.12.12 द्वारा NURM योजनान्तर्गत क्रमानुसार 185.27 लाख एवं 308.78 लाख की आवंटित राशि BUDA, Patna को उपलब्ध करायी गयी है। (नगर निकाय पत्रांक 757 दिनांक 21.11.14 द्वारा विभाग को सूचनार्थ)। (2) पुनः कुल 54.26 लाख की राशि DUDA Patna-2 को हस्तांतरित कर दी गयी है (पत्रांक-177 दिनांक 10.03.15)

7. नगर सेवा प्रबंधन :- आपके शहर में हेल्पलाईन के माध्यम से 28 जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 17 का निराकरण किया गया है, एवं 11 लंबित हैं। स्पष्टतः आपकी उपलब्धि **संतोषजनक** है।

8. होलिडिंग टैक्स :- माह फरवरी 2016 का मासिक संग्रहण 4.01 लाख रुपये है, जो की वित्तीय वर्ष की औसत मासिक संग्रहण 1.80 लाख रुपये से शत प्रतिशत अत्यधिक है। चालू वित्तीय वर्ष का वार्षिक औसत मासिक संग्रह 5.12 है। दिनांक 01.04.2015 को होलिडिंग की संख्या 10983 थी एवं अद्यतन तिथि तक 10983 होलिडिंग ही है। होलिडिंग का सर्वेक्षण करके अतिरिक्त होलिडिंग को होलिडिंग टैक्स के दायरे में लाने के लिए किये गये प्रयास जारी रहे। स्पष्टतः अब तक उपलब्धि **संतोषजनक** है।

9. अन्य स्रोतों से कर :-

अन्य स्रोतों से कर वसूली 8.28 लाख रुपये है, जिसमें सुधार लाने का प्रयास करें।

12. स्वच्छ भारत मिशन :-

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में दिए गए कुल लक्ष्य 174 के विरुद्ध आपके निकाय में एक भी सामूहिक एवं Public Toilet का निर्माण नहीं किया गया है। इस पर जोर दिया जाय।

14. सबके लिए आवास :- सबके लिए आवास योजनान्तर्गत आपके नगर निकाय में वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल प्राप्त आवेदन में से अधतन स्थिति तक जचोपरांत लाभार्थियों की संख्या 0 है।

15. पी०एल० खाता:-

दिनांक 01.04.2015 को आपके नगर निकाय के पी० एल० खाते में 1544.60 लाख रुपये उपलब्ध थे। वर्ष 2015-16 में 850.38 लाख राशि विमुक्त की गई है। इस प्रकार कुल उपलब्ध 2394.98 लाख की राशि में से 844.12 लाख मात्र राशि का भुगतान किया गया है। शेष 1550.86 लाख की अव्यवहृत अंतिम राशि (Closing Balance) अभी भी मौजूद है जो अत्यंत ही बड़ी राशि है।

निर्देश दिया जाता है कि इस मासिक समीक्षा टिप्पणी में अंकित तथ्यों पर लिखित अनुपालन प्रतिवेदन पत्र निर्गत होने के तीन सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से विभाग को प्रेषित किया जाय। इस मासिक समीक्षा टिप्पणी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। साथ ही आपके द्वारा समर्पित किये जा रहे मासिक समीक्षा टिप्पणी का अनुपालन प्रतिवेदन भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

विश्वासभाजन,

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक 8/4/16

ज्ञापांक-2487/

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, पटना/अध्यक्ष नगर परिषद् फुलवारीशरीफ एवं विभागीय मंत्री आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।

सचिव